भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1446

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**खाद्यान्नों का भंडारण**

1446. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्नों के भंडारण में वृद्धि हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) सरकार द्वारा खरीद का मौजूदा स्तर क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में खाद्यान्नों की भंडारण सुविधाओं और खाद्यान्नों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क):** खाद्यान्‍नों की खरीदारी बढ़ने के कारण और कवर तथा प्‍लिंथ में भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्‍य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्‍कीम तैयार की है। इस स्‍कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को सुनिश्‍चित किराया देने के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्‍य भंडारण निगमों के जरिए इस स्‍कीम के अधीन 19 राज्‍यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा दिनांक 15-10-2011 की स्‍थिति के अनुसार 69 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस स्‍कीम के अधीन केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्‍य भंडारण निगम क्रमश: 5.4 और 14.4 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्‍य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 4 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है।

सरकार ने 568.17 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में 5.4 लाख टन कुल अतिरिक्‍त भंडारण स्‍थान का निर्माण करने की स्‍कीम को भी अंतिम रूप दिया है।

**(ख)**: विपणन मौसम 2010-11 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई गेहूँ और चावल की खरीदारी निम्‍नानुसार है:-

गेहूं 225.14 लाख टनचावल 341.80 लाख टन

**(ग)**: भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का रखरखाव करने के लिए 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमश: 33.82 करोड़ रुपये और 39.19 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्‍नों का परिरक्षण करने के लिए 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमश: 35.07 करोड़ रुपये और 43.44 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया है।

\*\*\*\*\*\*\*